



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2015/फाल्गुन 1, 1936

No. 48]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2015/PHALGUNA 1, 1936

गृह मंत्रालय

(स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2015

सं. 2/16/2014-आर एंड एस ओ.— वर्ष 1947 में देश के विभाजन के परिणामस्वरूप, भारी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान में अपने संबंधित बैंकों में अपना बहुमूल्य सामान छोड़कर तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन किया था। इसी प्रकार, अनेक मुसलमान शरणार्थी भी इस देश के विभिन्न बैंकों में अपनी बहुमूल्य वस्तुएं छोड़ कर उस समय पाकिस्तान में प्रवासित हुए थे। ये बहुमूल्य सामान तत्कालीन निष्क्रांत संपत्ति के अभिरक्षक की अभिरक्षा में थे।

2. संबंधित बैंकों में पड़ी इन चल संपत्तियों को वापस करने के लिए वर्ष 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तत्पश्चात्, भारत सरकार ने निष्क्रांत धरोहर अधिनियम, 1955 का अंतरण नामक एक अधिनियम अधिनियमित किया। इस समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान के बैंकों में विस्थापित व्यक्तियों के लॉकरों के सामान तथा सुरक्षित धरोहरों को नवम्बर/दिसम्बर, 1961 में सील बन्द पैकटों में पाकिस्तान से भारत लाया गया था और उन्हें आर बी आई, नई दिल्ली की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। इन बहुमूल्य वस्तुओं का काफी सामान उनके मूल स्वामियों को वापस कर दिया गया है किन्तु अभी भी कुछ बहुमूल्य वस्तुएं रह गई हैं जिनका न तो दावा किया गया है और न ही उनके दावेदार दस्तावेज अथवा अन्य संतोषजनक प्रमाण दे पाए थे। मुस्लिम शरणार्थियों के आभूषणों के साथ यह संपत्ति विगत कई दशकों से आर बी आई के पास पड़ी हुई है।

3. वर्ष, 1965 में तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय ने भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायाधीश दिल्ली के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि न्यायालय द्वारा लॉकरों और सुरक्षित धरोहरों को वापस लिया जाए अथवा विकल्प के तौर पर, इन आभूषणों की देखभाल के लिए विभाग के स्थान पर एक नया ट्रस्टी नियुक्त किया जाए। जिला न्यायाधीश न्यायालय ने अगस्त, 1971 में यह आदेश पास किया कि इस मामले में नया ट्रस्टी नियुक्त करने का कोई बिंदु नहीं बनता है। चूंकि संपत्ति का दावा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है, इसलिए, अन्ततोगत्वा इसे भारत सरकार के पास राज सम्पत्ति के रूप में जमा करना पड़ेगा। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार सभी प्रकार के विक्रय धनार्जन में से इस पर देयराशि की कटौती कर लेगी और शेष सरकार के पास जमा हो जाएगी। न्यायालय ने आगे यह भी उल्लेख किया कि दावा न किये गए लॉकरों और सुरक्षित सामान की देखभाल करने के लिए नया ट्रस्टी नियुक्त करने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा।

4. न्यायालय के इस आदेश के पश्चात्, विभाग ने विधि मंत्रालय की राय मांगी। विधि मंत्रालय ने यह सलाह दी कि नैसर्गिक न्याय के हित में किसी शेष रह गए दावेदार को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए। इसके परिणामस्वरूप, विभाग ने 1979 और 1991 में दो सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित की। इन सार्वजनिक सूचनाओं के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आवेदनों की दुबारा जांच की गई और सही दावेदारों के अभाव में कोई भी लॉकर वापस नहीं किया जा सका।

5. विधि मंत्रालय के पश्चात् विदेश मंत्रालय से भी राजनीतिक स्वीकृति के लिये अनुरोध किया जो मिल गई थी। तत्पश्चात्, 1990 में यह विचार किया गया कि कोई निर्णय लेने से पहले आर बी आई के पास पड़े इन बॉक्सों में रखी सभी वस्तुओं की एक सम्पत्ति सूची तैयार की जाए। तथापि, यह प्रयास तब विपश्चित हो गए जब ए एन जेड ग्रिडले बैंक और एस बी आई भी यह सूचित करने के लिए सामने आए कि उनके पास भी कुछ लॉकर और सामान हैं और उन्होंने मंत्रालय से उन्हें वापस लेने का अनुरोध किया। ए एन जेड ग्रिडले बैंक बनाम भारत संघ (सिविल याचिका 1132/90) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1991 के निर्णय के तहत भारत संघ को यह निदेश दिया कि वह इन संपत्तियों को राज संपत्ति के रूप में ले ले क्योंकि अब कोई भी वैध दावेदार नहीं है। अतः मंत्रालय ने सर्वप्रथम इन बैंकों के बॉक्सों की एक संपत्ति-सूची निकाली और उन्हें आर बी आई के पास जमा करा दिया। अन्ततः, मंत्रालय एक समेकित संपत्ति सूची तैयार करने की स्थिति में था।
6. इसके पश्चात्, मंत्रालय, आर बी आई से अधिकारियों और स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शामिल करते हुए एक समिति का गठन करके बॉक्सों की एक समेकित संपत्ति सूची तैयार की गई थी। संपत्ति-सूची तैयार करने की प्रक्रिया जनवरी, 2015 में पूरी हो गई थी।
7. यह स्पष्ट है कि जहां भी असली दावेदार पाए गए थे उन्हें उनके दावों के अनुसार सामान वापस कर दिये गए थे। शेष सामान आर बी आई के पास विगत कई दशकों से पड़े हैं। मंत्रालय द्वारा 1979 और इसके पश्चात् 1991 में विज्ञापन जारी करने के बावजूद, कोई वैध दावेदार आगे नहीं आया है। इसलिए, आज की स्थिति में, न तो कोई असली दावा और न ही दावा मामलों के संबंध में ऐसा कोई विवाद लंबित है जो पहले अस्वीकार किए गए थे। उपर्युक्त तथ्यों और जिला न्यायाधीश, दिल्ली के निर्णय के आलोक में, इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है कि इन बॉक्सों में रखे सामान का कोई और दावेदार है और इस प्रकार, सभी सामान दावा रहित हैं। इन सभी वर्षों में किये गए प्रयासों के माध्यम से केन्द्र सरकार उक्त वस्तुओं के संबंध में एक प्रभावकारी ट्रस्टी के रूप में कार्य करती रही है।
8. जबकि उक्त संपत्ति एक प्रभावकारी ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही भारत सरकार के पास, भारतीय रिजर्व बैंक में लंबे समय से है और किसी व्यक्ति द्वारा इनके संबंध में कोई वैध दावा नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता है कि उक्त संपत्ति को राजगत संपत्ति के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, 'दावा रहित संपत्ति' के रूप में घोषित किया जाए।
9. जबकि उक्त संपत्ति के लिए न तो कोई दावा प्रस्तुत किया गया है और न ही अस्वीकृत मामले के संबंध में कोई कानूनी विवाद लंबित है, इसलिए, भारत सरकार इस आदेश द्वारा उक्त संपत्ति को 'दावा रहित संपत्ति' के रूप में घोषित करती है और यह भी घोषित करती है कि उक्त संपत्ति का स्वामित्व सभी आशयों एवं प्रयोजनों के लिए अब भारत सरकार में निहित हो जाएगा।
10. यह कि उक्त संपत्ति से संबंधित सभी अधिकारों को अब भारत सरकार में निहित किया जा रहा है। इसलिए, केन्द्र सरकार अब इन बॉक्सों में मौजूद सामान का निपटान उस तरीके से करने के लिए सक्षम है जैसा भी वह उचित समझे।
11. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(FREEDOM FIGHTERS AND REHABILITATION DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi the 20th February, 2015

No. 2/16/2014-R&SO.—In the aftermath of partition of the country in 1947, a large number of people had migrated from the then West Pakistan leaving behind their valuables in their respective banks in Pakistan. Similarly, many Muslim evacuees, had migrated to Pakistan at that time leaving behind their valuables in various banks in this country. These were under the custody of the then Custodian of Evacuee Property.

2. In order to return these moveable properties lying in the respective banks, an Agreement was signed between India and Pakistan in 1950. Thereafter, the Government of India enacted an Act called the Transfer of Evacuee Deposits Act, 1955. Under the said Agreement, the contents of lockers and safe deposits of displaced persons with the banks in West Pakistan were brought from Pakistan to India in sealed packets in November/December, 1961 and were kept in safe custody of the RBI, New Delhi. A major portion of these valuables have been restored to their original owners but there were still some valuables which have either not been claimed or where the claimants were unable to furnish documentary and other satisfactory proofs. This, together with the jewellery of Muslim Evacuees, have been lying with the RBI since the past many decades.

3. In 1965, the then Ministry of Rehabilitation filed an Application under the Indian Trusts Act before the District Judge, Delhi praying that lockers and safe deposits be taken over by the Court or alternatively, a new Trustee in place of the Department be appointed to take care of these jewellery. The Court of District Judge passed an order in August, 1971 that there is no point in appointing a new Trustee. Since no one is coming forward to claim the property, the property ultimately has to be escheated to the Government of India. The Court noted that the Government will deduct

from the sale proceeds all sorts of amounts due to it and the residue shall stand escheated to the Government. The Court further noted that it will serve no useful purpose to appoint a new Trustee to administer the contents of the unclaimed lockers and safe.

4. After this Order of the Court, the Department sought the views of the Ministry of Law. The Ministry of Law advised that in the interest of natural justice, public notices be issued to invite any remaining claimants. As a result, the Department took out two Public Notices in 1979 and in 1991. All the applications received in response to these public notices were again examined and no lockers could be released for want of rightful claimants.

5. After the Ministry of Law, the Ministry of External Affairs was also approached for political clearance, which was obtained. It was thought then, in 1990s, to prepare an inventory of all the contents in these boxes lying with RBI before an informed decision could be taken. However, these efforts got distracted when the ANZ Grindlays Bank and SBI too came forward to inform that they had some lockers/articles with them and asked the Ministry to take back these items. In ANZ Grindlays Bank V/s UOI (CW 1132/90), the Delhi High Court vide its judgement dated 8th August, 1991 directed the Union Government to take over the property as an escheat since there are no more valid claimants. The Ministry, therefore, first drew the inventory of the boxes of these banks and deposited them with the RBI. Finally, the Ministry was in a position to prepare a consolidated inventory.

6. Subsequently, a consolidated inventory of the boxes was prepared by constituting a Committee comprising officers from the Ministry, RBI and local Executive Magistrate. The process of preparing the inventory was completed in January, 2015.

7. It is clear that whenever genuine claimants were found, they were handed over the items as per their claims. The remaining items have been lying with the RBI since the last many decades. No valid claimant came forward in spite of the Ministry taking out advertisements, once in 1979 and then in 1991. Therefore, as on date, there is neither a genuine claim pending nor any dispute in regard to the claim cases, which were rejected earlier. Given the above fact and in light of the judgement of the District Judge, Delhi, it is highly improbable that there are any more claimants for the contents of these boxes and as such all the contents stand unclaimed. All through these years, the Central Government has been acting as a constructive trustee of the said contents.

8. Whereas the said property is in the possession of the Reserve Bank of India since a very long time with the Government of India as a Constructive Trustee and since there is no valid claim being preferred by any person, therefore, it appears to be just and reasonable to declare the said property as 'Unclaimed Property' in terms of the General principles of escheatment.

9. Whereas no claim has been preferred for the said property nor any legal dispute for the rejected cases is pending, therefore, the Government of India, by this order, hereby declares the said property as 'Unclaimed Property' and declares that the ownership of the said property shall now be vested in the Government of India for all intents and purposes.

10. That all the rights with respect to the said property are now being vested in the Government of India. Therefore, the Central Government is now competent to dispose of the contents in these boxes in such manner as it deems fit.

11. This issues with the approval of the Competent Authority.

K.K. PATHAK, Jt. Secy.